



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2011/आषाढ़ 30, 1933

No. 410]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2011/ASADHA 30, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. 35/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 560(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में अनिवार्य है, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 96(अ), दिनांक 1 मार्च, 2006 के जरिए प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 6/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006 में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में अनुबंध में,—

क. शर्त सं. 26 और इससे संबंधित प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“यदि,—

(क) ऊर्जा मंत्रालय में भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव श्रेणी का अधिकारी परियोजना को अल्ट्रा मेगा ऊर्जा परियोजना के रूप में प्रमाण पत्र देता है;

(ख) उपर्युक्त के रूप में अल्ट्रा मेगा ऊर्जा परियोजना की स्थिति के संबंध में जारी प्रमाण पत्र अस्थायी होता है तो परियोजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार प्राप्त उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, के समक्ष केवल इस छूट को छोड़कर देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य राशि के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम छः महीने की अवधि के

लिए किसी अनुसूचित बैंक से मियादी जमा रसीद के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और यदि परियोजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्पाद शुल्क के माल की निकासी की तिथि से छत्तीस महीने की अवधि के अंदर अंतिम अल्ट्रा मेगा ऊर्जा स्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उक्त प्रतिभूति इस छूट को छोड़कर ऐसी निकासियों पर देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए उपयोग कर ली जाएगी;

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कम से कम मुख्य इंजीनियर की श्रेणी का अधिकारी माल की मात्रा, उनका विवरण और उनकी विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए यह प्रमाण पत्र देता है कि उक्त माल भारत सरकार के अंतर्गत उक्त अल्ट्रा मेगा ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित है;

(घ) परियोजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार प्राप्त उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र देता है कि—

(i) उक्त माल का उपयोग केवल उक्त परियोजना में किया जाएगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं; तथा

(ii) उपर्युक्त उप-खंड (i) का अनुपालन नहीं किए जाने पर परियोजना डेवलपर इस छूट को छोड़कर माल की निकासी के समय उद्ग्राह्य शुल्क का भुगतान करेगा।”

ख. शर्त सं. 28 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“यदि,—

(क) ऊर्जा मंत्रालय में भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव श्रेणी का अधिकारी परियोजना को मेगा ऊर्जा परियोजना के रूप में प्रमाण देता है;

(ख) उपर्युक्त के रूप में मेगा ऊर्जा परियोजना की स्थिति के संबंध में जारी प्रमाण पत्र अस्थाई होता है तो परियोजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार प्राप्त उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, के समक्ष केवल इस छूट को छोड़कर देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य राशि के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम छः महीने की अवधि के लिए किसी अनुसूचित बैंक से मियादी जमा रसीद के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और यदि परियोजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्पाद शुल्क के माल की निकासी की तिथि से छत्तीस महीने की अवधि के अंदर अंतिम मेगा ऊर्जा स्थिति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उक्त प्रतिभूति इस छूट को छोड़कर ऐसी निकासियों पर देय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए उपयोग कर ली जाएगी;

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कम से कम मुख्य इंजीनियर की श्रेणी का अधिकारी माल की मात्रा, उनका विवरण और उनकी विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए यह प्रमाण पत्र देता है कि उक्त माल भारत सरकार के अंतर्गत उक्त मेगा ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए अपेक्षित है;

(घ) परियोजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार प्राप्त उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र देता है कि—

(i) उक्त माल का उपयोग केवल उक्त परियोजना में किया जाएगा, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं; तथा

(ii) उपर्युक्त उप-खंड (i) का अनुपालन नहीं किए जाने पर परियोजना डेवलपर इस छूट को छोड़कर माल की निकासी के समय उद्ग्राह्य शुल्क का भुगतान करेगा।"

[फा. सं. 354/94/2011-टीआरयू]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

**टिप्पण :**—मूल अधिसूचना सं. 6/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 96(अ), दिनांक 1 मार्च, 2006 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 26/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 24 मार्च, 2011 द्वारा सं. सा.का.नि. 238(अ), दिनांक 24 मार्च, 2011 के जरिए किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2011

No. 35/2011-Central Excise

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 96(E), dated 1st March, 2006, namely :—

In the said notification, in the ANNEXURE,—

A. for Condition No. 26, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"If,—

- (a) an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power certifies the project as Ultra Mega Power Project;
- (b) in case the certificate regarding Ultra Mega Power Project status issued as above is provisional, the Chief Executive Officer of the project furnishes a security in the form of a Fixed Deposit Receipt from any Scheduled Bank for a term of thirty six months or more, in the name of the President of India for an amount equal to the Central Excise Duty payable but for this exemption, to the Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction and if the Chief Executive Officer of the project fails to furnish the final Ultra Mega Power status certificate within a period of thirty six months from the date of clearance of excisable goods, the said security shall be appropriated towards Central Excise Duty payable on such clearances but for this exemption;
- (c) an officer not below the rank of Chief Engineer in the Central Electricity Authority certifies that the said goods are required for the setting up of the said Ultra Mega Power Project under the Government of India initiative, indicating the quantity, description and specification thereof;
- (d) the Chief Executive Officer of the project furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction, to the effect that—
  - (i) the said goods will be used only in the said project and not for any other use; and
  - (ii) in the event of non-compliance of sub-clause

(i) above, the project developer will pay the duty which would have been leviable at the time of clearance of goods, but for this exemption.”

- B. for Condition No. 28, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“If,—

- (a) an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power certifies the project as Mega Power Project;
- (b) in case the certificate regarding Mega Power Project status issued as above is provisional, the chief executive officer of the project furnishes a security in the form of a Fixed Deposit Receipt from any Scheduled Bank for a term of thirty six months or more, in the name of the President of India for an amount equal to the Central Excise Duty payable but for this exemption, to the Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction and if the project developer fails to furnish the final Mega Power status certificate within a period of thirty six months from the date of clearance of excisable goods, the said security shall be appropriated towards Central Excise Duty payable on such clearances but for this exemption;
- (c) an officer not below the rank of Chief Engineer in the Central Electricity Authority certifies that the said goods are required for the setting up of the said Mega Power Project under the Government of India initiative, indicating the quantity, description and specification thereof;
- (d) the Chief Executive Officer of the project furnishes an undertaking to the Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction, to the effect that—
  - (i) the said goods will be used only in the said project and not for any other use; and
  - (ii) in the event of non-compliance of sub-clause (i) above, the project developer will pay the duty which would have been leviable at the time of clearance of goods, but for this exemption.”

[F. No. 354/94/2011-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.

Note :—The principal notification No. 6/2006-Central Excise dated the 1st March, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 96(E), dated the 1st March, 2006 was last amended *vide* notification No. 26/2011-Central Excise, dated the 24th March, 2011, published *vide* number G.S.R. 238(E), dated the 24th March, 2011.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

सं. 65/2011-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 561(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002, जिसे सा.का.नि. 118(अ) दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, शर्त सं. 86 में, खंड (क) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, यथा:—

“(कक) परियोजना के लिए ऐसे आयात के मामले में जिसके लिए ऊर्जा मंत्रालय में भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव की श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी मेगा ऊर्जा परियोजना स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र अस्थाई होता है, आयातक आयात के समय सीमा शुल्क के उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, के समक्ष इस छूट को छोड़कर ऐसे आयात पर देय सीमा शुल्क के समतुल्य राशि के लिए भारत के राष्ट्रपति के नाम छत्तीस महीने अथवा अधिक की अवधि के लिए किसी अनुसूचित बैंक से मियादी जमा रसीद के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा और यदि आयातक आयात की तिथि से छत्तीस महीने की अवधि के अंदर अंतिम मेगा ऊर्जा स्थिति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उक्त प्रतिभूति इस छूट को छोड़कर ऐसे आयात पर देय सीमा शुल्क के लिए उपयोग कर ली जाएगी।”

[फा. सं. 354/94/2011-टीआरयू]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना को सा.का.नि. 118(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के जरिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 63/2011-सीमा शुल्क, दिनांक 19 जुलाई, 2011 जिसे सा.का.नि. सं. 549(अ), दिनांक 19 जुलाई, 2011 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2011

No. 65/2011-Customs

G.S.R. 561(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, which was published in the Gazette of

India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002, namely:—

In the said notification, in the Annexure, in Condition No. 86, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

“(aa) In case of imports for a project for which the certificate regarding Mega Power Project status issued by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power is provisional, the importer furnishes a security in the form of a Fixed Deposit Receipt from any Scheduled Bank for a term of thirty six months or more in the name of the President of India for an amount equal to the duty of customs payable on such imports but for this exemption, to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at

the time of importation and if the importer fails to furnish the final Mega Power status certificate within a period of thirty six months from the date of importation, the said security shall be appropriated towards duty of customs payable on such imports but for this exemption.”.

[F.No. 354/94/2011-TRU]]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 63/2011-Customs, dated the 19th July, 2011 which was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 549(E), dated the 19th July, 2011.